

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 08 फरवरी, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में नगरपालिका परिषद, टनकपुर (जिला-चम्पावत) को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, टनकपुर के पत्रांक-749/अवस्थापना वि0नि0/2015-16, दिनांक 29.12.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, टनकपुर के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु कार्यवार गठित आगणन ₹45.84 लाख के टी0ए0सी0 (वित्त विभाग) द्वारा परीक्षणोंपरान्त संस्तुत धनराशि कुल ₹44.39 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल ₹30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
1-	चावल पड़ाव में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य।	34.26	22.00
2-	बूचड़खाने में दुकानों का निर्माण कार्य।	10.13	8.00
योग-		44.39	30.00

- उक्त धनराशि कुल ₹30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगरपालिका परिषद, टनकपुर को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹30.00 लाख के अतिरिक्त शेष धनराशि ₹14.39 लाख का वहन नगरपालिका परिषद, टनकपुर द्वारा योजनाओं से प्राप्त होने वाली आय/स्वयं के स्रोतों से वहन किया जायेगा।
- नगर निकाय द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित होने वाली दुकानों की नीलामी नियमान्तर्गत खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर कराते हुए अधिकतम प्रीमियम प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
- आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

- VII. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- VIII. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
- IX. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- X. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।
- XI. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- XII. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
- XIII. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
- XIV. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- XV. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।
- XVI. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले **Construction Agreement** में एक वर्ष का **Defect Liability Period** तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- XVII. धनराशि का दिनांक 31-3-2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-"नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०- 689/XXVII(2)/2015, दिनांक 01.02.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- अलॉटमेंट आई डी-S..८८२.../३६२/२..

भवदीय,

(डी०एस० गर्बाल)
सचिव।

संख्या-२२१ (1)/IV(2)-शा०वि०-2015, तददिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।

3. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, चम्पावत।
7. वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, टनकपुर।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।